

**विवाद पर विवाद
ने निकाली
पार्टी की जान**

प्रदेश अध्यक्ष तक चुनना हुआ मुश्किल

लगभग हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस

नई दिल्ली- कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही हैं। एक विवाद निपटाने की कोशिशें चल ही रही होती हैं कि नया विवाद सामने आन खड़ा होता है। पहले पंजाब तो फिर अचानक से हरियाणा में हुड्डा समर्थकों का कुमारी शैलेजा के खिलाफ खड़ा होना नई गुटबाजी लेकर सामने आ गया। गांधी परिवार के लिए मुश्किलों का दौर खत्म हाने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले सत्ता विहीन अब पार्टी में बढ़ती अंतरकलह दीमक की तरह पार्टी को चाटती चली जा रही है और कांग्रेस सुप्रिमो सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर पा रहे। वर्तमान में पंजाब विवाद अभी सुलझा नहीं है, वहीं दूसरे राज्यों में आंतरिक कलह जोर पकड़ने लगी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति है क्योंकि, राज्यों में गुटबाजी चरम पर है।



तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी पंजाब विवाद को हल करने में नाकाम है। कई माह की मशकत के बावजूद कलह बरकरार है। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में सहमति नहीं बन पाने की वजह से विवाद बढ़ रहा है। पार्टी का आंतरिक

झगड़ा सिर्फ इन दो प्रदेशों तक सीमित नहीं है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड सहित कई दूसरे प्रदेशों में भी विवाद है। बिहार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा की है।

ताकि, किसी तरह का विवाद न हो। पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। वह चौधरी को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। पर नया अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर एक राय नहीं है। सभी अपनी-अपनी दावेदारी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक के बाद एक प्रदेश में शुरू हो रही अंदरूनी कलह की एक वजह पार्टी अध्यक्ष को लेकर अनिश्चितता है। पद की दावेदारी करने वाले सभी नेता और गुट पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इससे कलह बढ़ती है। कांग्रेस के रणनीतिकार भी मानते हैं कि पार्टी नेतृत्व को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से मिलना शुरू किया है। इसका लाभ मिलेगा, पर उन्हें अपना दायरा बढ़ाथे हुए जल्द निर्णय लेने होंगे।

लकायदा बन रहा भारत के लिए बड़ा खतरा

केरल-बंगाल और अब लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के क्या हैं संकेत?

नई दिल्ली-अलकायदा से जुड़े अंसार गजवा तुल हिंद के आतंकी भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। हालांकि, अब तक सुरक्षा एजेंसियों की सजगता से आतंकीयों का कोई बड़ा प्लान सफल नहीं हो पाया है। लेकिन सुरक्षा जानकार मानते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इनका फैलना खतरनाक संकेत है। सितंबर 2020 में एनआईए ने केरल और बंगाल से नौ अलकायदा आतंकीयों के पकड़ने का दावा किया था। इनके हैंडलर भी पाकिस्तान में बताए गए थे। जानकार मानते हैं कि बड़ी

चुनौती इनके विदेशी आकाओं तक पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित करवाना है। ठोस सबूतों के जरिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की जरूरत है। क्योंकि, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक योजना भारत में कट्टरपंथ के जरिये ऐसे संगठनों को विस्तार देने की है। हैंडलर्स तक पहुंचना होगा बीएसएफ के पूर्व एडीजी व सुरक्षा मामलों के जानकार पीके मिश्रा का कहना है कि अलकायदा के स्लीपर सेल देश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। इनकी फंडिंग के स्रोत को खत्म करने और

इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इनके हैंडलर्स तक पहुंचना होगा। पूर्व एडीजी का कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप (एक्यूआईएस) को फंडिंग कर रहा है। जानकारों का कहना है कि पहले भी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि कट्टरपंथ की आग सुलगाकर अलकायदा और आईएस गठजोड़ से भारत के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी हमलों की योजना बनाई गई है। पूर्व एडीजी ने कहा, केंद्रीय व विभिन्न राज्यों की एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है।
कई राज्यों में स्लीपर सैल सक्रिय- पूर्व एडीजी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, केरल और कश्मीर में अलकायदा के सबसे

ज्यादा स्लीपर सैल हैं। यूपी, बिहार और हरियाणा में भी इनके नेटवर्क की सूचना एजेंसियों के पास पहले से है। कहीं पर अलकायदा है तो कहीं आईएस प्रेरित आतंकी संगठन की मौजूदगी है।
यूएन की रिपोर्ट में किया गया था आगाह-आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें यह दावा किया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के 180 से 200 आतंकी हैं। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आईएस का सहयोगी है।

अहमदाबाद के शिव मंदिर में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़

नंदी की मूर्ति और शिवलिंग क्षतिग्रस्त, संगठनों ने की कार्रवाई की मांग



मलेरकोटला- मलेरकोटला जिले के अहमदाबाद के सरौद गांव में 10 जुलाई को शिव मंदिर में तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया। मंदिर में शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 9 जुलाई और 10 जुलाई की रात को हुई इस घटना की रिपोर्ट पूर्व कप्तान परमजीत कुमार ने दी थी, जो मंदिर की देखरेख कर

रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जब कुमार अपने परिवार के साथ मंदिर का द्वार खोलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग टूटा हुआ था और उसका एक हिस्सा बाहर पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक (स्व) अमनदीप सिंह बराड़ और एसपी हर्षीत सिंह हुंदल मौके पर पहुंचे। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, हिंदू संगठनों ने मंदिर

के पास भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में डीएसपी संदीप वडेरा, डीएसपी अमरगढ़ राजन शर्मा, एसएचओ हरमेश सिंह, एसएचओ विनरजीत सिंह और थाना प्रभारी हरमीत सिंह की निगरानी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मलेरकोटला के जिलाध्यक्ष अमन थापर ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में भगवान नंदी की मूर्ति और शिवलिंग की तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा, प्रशासन ने मंदिर परिसर को बंद कर दिया है। हम मांग करते हैं कि पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को गिरफ्तार करे। थापर ने आगे कहा कि पंजाब में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में राज्य में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की खबर आई थी। उन्होंने कहा, यह राज्य में समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का एक प्रयास है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नुकसान जानवरों के कारण हो सकता है, लेकिन थापर के अनुसार, अपराधियों ने

नुकसान पहुंचाने के लिए शायद किसी तेज उपकरण का इस्तेमाल किया था। बजरंग दल संगठन के धर्म प्रचारक विजय ढोलेवाल ने कहा कि हिंदुओं ने हमेशा अन्य धर्मों का स्वागत किया है, लेकिन अब हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह एक प्राचीन मंदिर है। हिंदू समाज आक्रोशित है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अपराधी गिरफ्तार होते हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएँ क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव के लिए अच्छी नहीं हैं और पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जागरण ने एसपी हुंदल के हवाले से कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।

बीएसएफ कमांडेंट के फ्लैट में चला रहा था नशे का कारोबार

2500 करोड़ की हैरोइन का मामला, सोसाइटी के गार्ड से संपर्क कर लिया था फ्लैट

फरीदाबाद- फरीदाबाद से गिरफ्तार नशे के सौदागरों ने चौकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी नशे के कारोबार के लिए फ्लैट नंबर 402 में रह रहे थे, जो कि बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नवल सिंह के नाम पर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल ने शुक्रवार रात सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार और फ्लैट से 351 किलोग्राम हैरोइन बरामद की थी। आरोपियों ने चार कमरों वाले इस फ्लैट को महज 14 हजार रुपये प्रतिमाह के किराये पर लिया था।

जांच में पता चला है कि फ्लैट मालिक ने किरायेदारों का पुलिस वरिफिकेशन भी नहीं कराया था। पुलिस ने फ्लैट मालिक को नोटिस जारी किया है। एनएसजी विहार सोसाइटी में मात्र बीस फ्लैट हैं, जो सेना व आर्म्ड फोर्स के अधिकारियों के नाम पर हैं। यहां एक फ्लैट आईपीएस का भी है। सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर ही एक बोर्ड पर सभी अधिकारियों के फ्लैट नंबर व नाम लिखे हैं। सोसाइटी के चौथे फ्लोर पर बना फ्लैट नंबर 402



नवल सिंह के नाम पर है, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अधिकारी हैं। सूत्रों के मुताबिक नवल सिंह फिलहाल बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर

तैनात हैं। पुलिस गिरफ्त में आए अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर जालंधर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी व गुरजोत सिंह उर्फ गोलू इसी फ्लैट में रहते थे। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी व गुरजोत सिंह उर्फ गोलू ने फ्लैट किराए पर लेने के लिए सोसाइटी के गार्ड से संपर्क किया था। गार्ड ने उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर दे दिया था। डीलर ने नवल सिंह से बात कर आरोपियों को फ्लैट दिलाया। वारदात के बाद से सोसाइटी के एक सुरक्षाकर्मी को हटा दिया गया है।

किसी से बातचीत नहीं करते थे सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर रहे एक युवक ने बताया कि 402 नंबर फ्लैट में रह रहे लोग किसी से बातचीत नहीं करते थे। सोसाइटी व आसपास के लोगों को घटना के बाद तक नहीं पता लगा था कि माजरा क्या है। टीवी में देखने का बाद सभी हैरान थे। थाना आदर्श नगर प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिनों पहले ही यहां रहना शुरू किया था। फ्लैट के मालिक को नोटिस जारी किया गया है।

दोआबा रिपोर्टर
दोआबा रिपोर्टर समाचारपत्र तथा बेव टीवी के लिए पंजाब के सभी जिलों, कस्बों से पत्रकारों/फोटोग्राफरों/विशेष प्रतिनिधियों और ब्यूरो चीफ व मार्केटिंग के लिए लड़के/लड़कियों की आवश्यकता है।
(चाहवान सम्पर्क करें)
(मो.) 7009010789

दोआबा रिपोर्टर

भारत सरकार द्वारा पंजीकृत

मुख्य सम्पादक : श्री संजीव शर्मा

RNI No. PUNHIN/2004/13985

News Portal: www.doabareporter.com



doabareporter.com

सोमवार, 12
जुलाई 2021



7009010789 - 94175-85949

**उपभोक्ता फोरम ने
बीमा कंपनी को वलेम
देने का दिया आदेश**

सिर्फ गंध से शराब पीना नहीं होता साबित



चंडीगढ़— चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम ने कहा कि शराब की गंध आने से यह साबित नहीं होता कि शख्स ने शराब पी है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह शख्स अपनी देखभाल नहीं कर सकता या वह गाड़ी नहीं चला सकता। यह कहते हुए फोरम ने एक कार ऐक्सिडेंट के मामले में एक पीड़ित को बीमा की रकम 1.84 लाख रुपये देने का आदेश दिया, जिसे बीमा कंपनी ने

खारिज कर दिया था। राजन दीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 31 मई, 2018 से 30 मई, 2019 की अवधि के लिए 8 लाख रुपए के आईडीवी के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस से बीमा लिया था। 1 फरवरी 2019 की आधी रात को कोहरे के कारण सैक्टर-34/35 के पास उनका ऐक्सिडेंट हो गया। उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वह 3 फरवरी, 2019 तक

अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी कार का बीमा कैशलेस था इसलिए उन्होंने 10,000 रुपये का भुगतान करके अपनी गाड़ी ले ली।

22 मई 2019 को मिला बीमा कंपनी से पत्र

14 मार्च, 2019 को राजन के पास हंडर्ड डीलरशिप से 1,61,178 रुपये के बाकी भुगतान करने का कॉल आया। उन्हें बताया गया कि बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया है। उन्हें 1,61,178 रुपये का भुगतान करना पड़ा। 22 मई 2019 को उन्हें लेटर मिला जिसमें बताया गया कि उनका बीमा क्लेम इसलिए खारिज किया गया क्योंकि वह शराब या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहे थे।

दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा...

आयोग ने दलीलें सुनने के बाद कहा, %बीमा कंपनी शिकायतकर्ता की मैडीकल जांच रिपोर्ट के रूप में कोई टोस और विश्वसनीय साक्ष्य रेकॉर्ड में लाने में सक्षम नहीं रही है जिससे यह साबित हो सके कि दुर्घटना के समय वह शराब के नशे में था और खुद की देखभाल करने या गाड़ी चलाने में असमर्थ था।

नहीं हुई ब्लड की जांच

आयोग ने कहा, शराब की मात्रा की पुष्टि के लिए ब्लड की जांच किए बिना शिकायतकर्ता से आने वाली कुछ दुर्गंध के आधार पर उपचार करने वाले चिकित्सक की टिप्पणियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कहीं भी शराब की मात्रा का उल्लेख नहीं था, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि शिकायतकर्ता नशे में था या वह नशे के प्रभाव में वाहन चलाने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था।

मेष राशि वालों के सारे काम आसानी से होंगे पूरे

आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और दिन सोमवार है। द्वितीया तिथि सुबह 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक वज्र योग रहेगा। साथ ही देर रात 3 बजकर 15 मिनट तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा।
मेष- दिन सामान्य रहेगा। इस राशि के बिल्डर्स को धनलाभ होगा साथ ही नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। पहले से बनायी हुई सारी योजनाएँ पूरी हो जाएंगी।
वृष-दिन सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। किसी जरूरी काम के पूरा होने पर बधाईयाँ देने के लिए लोगों का आवागमन

लगा रहेगा। अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है।
मिथुन-दिन बैस्ट है। कई दिनों से आपकी तख्तों में आ रही रूकावटें दूर हो जाएंगी। परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। जीवनसाथी को कहीं बाहर घूमने ले जाने का वादा कर सकते हैं।
कर्क- दिन आप के लिए अनुकूल रहेगा। ऑफिस में किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ सकती हैं। सामने आयी सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे तो सफलता भी हाथ लगेगी।



सिंह- जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी काम को करने में जल्दबाजी करने से बचें। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है।

कन्या-तकदीर आपके साथ रहेगी। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो किसी के मदद से पूरा हो जाएगा। किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें।
तुला- दिन खुशियों से भरा रहेगा। परिवारिक रिश्तों में

मिठास आएगी। बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
वृश्चिक-आपका मन पूजा-पाठ में अधिक लगा रहेगा। माता-पिता के साथ मंदिर में जाने का प्लान बना सकते हैं। कई दिनों से चली आ रही परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं।
धनु-दिन स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। सरकारी नौकरी के लिए एजाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सफलता मिलना निश्चित है। घर का

माहौल खुशुमाना बना रहेगा।
मकर-आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। लॉ के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स अपने समय का सदुपयोग करें। कॉलेज से मिले प्रोजेक्ट को सीनियर्स की मदद से पूरा कर लीजिए वरना टीचर्स से आपको डांट पड़ सकती है।
कुम्भ-अगर आप नौकरी कर रहे तो ट्रांसफर किसी ऐसे स्थान पर हो सकता है, जहाँ से अप-एण्ड-डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी।
मीन-दिन बहुत अच्छा रहेगा। सड़क पर चलते समय आप सतर्क रहें। इस राशि छात्रों के लिए दिन अच्छा है उनकी पढ़ाई में आ रही बाधाएँ दूर हो जाएगी।

घोटालों में डूबे बैंक, सालों से राजनीतिक कब्जा

जानिए अमित शाह को सहकारिता की कमान से विपक्ष क्यों बेचैन?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में दी गई बड़ी जिम्मेदारी



363 जिला सहकारी और 33 राज्य सहकारी बैंक इस काम में लगे

363 जिला सहकारी और 33 राज्य सहकारी बैंक इस काम में लगे हुए हैं। 2019-20 में देश में 1539 शहरी सहकारी बैंक थे। साथ ही 95,238 ऐसी सोसाइटियां थीं। हालांकि, सहकारिता के विकास में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। राज्यों में सहकारी आयुक्त के साथ-साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज भी होते हैं, जो इन सहकारी समितियों के संचालन का औपचारिक कार्य करते हैं। पूरे देश में सहकारिता का मॉडल अभी तक अच्छे से लागू नहीं हो पाया है और अमित शाह की बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि इससे जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए और उत्साहित किया जाए। अब केंद्र सरकार इनके लिए नियम-कानून बनाएगी और जनता के लिए काम होगा, जिससे इन्हें प्राइवेट कंपनियों की तरह चला रहे इन राजनीतिक दलों और चंद नेताओं का प्रभाव कम होगा।

विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा

केंद्र सरकार ने कहा, यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'कारोबार में सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। समुद्राय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ही इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। अब इसे पूरा किया गया है। बहुराज्यीय सहकारी समितियों को अब इस मंत्रालय से सीधे मदद मिलेगी। बैंकिंग, खेती, चीनी मिल संचालन और डेयरी फार्मिंग जैसे कई क्षेत्र हैं, जहां लोग सहकारी संस्था बना कर साझा लक्ष्य के लिए अपना-अपना योगदान देते हैं। सहकारिता का प्रभाव इसी से समझ लीजिए कि देश में फिलहाल 1.94 लाख कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी और 330 चीनी मिल एसोसिएशन हैं। गुजरात की सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अमूल ब्रांड को इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। भारत में कृषि में मदद के लिए ग्रामीण स्तर पर किसानों द्वारा कई 'प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज' का गठन किया जाता है। किसानों को इससे सुगमता से कर्ज उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए जिला एवं राज्य स्तर पर सहकारी बैंक होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नए सहकारिता (Cooperation) मंत्रालय के गठन का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इससे विपक्ष बेचैन हो गया है। विपक्ष को डर है कि सहकारिता से विकास का मंत्र पूरे भारत में लागू होने पर गरीब किसान और लघु व्यवसायी बड़ी संख्या में सशक्त होंगे, जिससे भाजपा और मजबूत होगी। सबसे पहले तो यह जानिए कि भारत सरकार ने आखिर सहकारिता के रूप में एक नए मंत्रालय की जरूरत क्यों समझी। केंद्र ने मंगलवार (जुलाई 6, 2021) को इसके गठन की घोषणा की और शुक्रवार को पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को इसकी कमान दी गई। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। देश में सहकारिता आंदोलन को ये मंत्रालय मजबूत करेगा। लेकिन, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये सहकारिता आंदोलन को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा व वातावरण प्रदान करे। यह मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।

अमित शाह के मंत्री बनने से विपक्ष बेचैन क्यों?

आखिर विपक्षी को बेचैनी का कारण क्या है कि वो केंद्र सरकार के इस नए पहलू का स्वागत करने की बजाय इसका विरोध कर रहा है। कॉंग्रेस का कहना है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेत्रिथला ने की इस 'चेतावनी' के बाद कॉंग्रेस ने इस पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। उसकी योजना है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले सब कुछ खंगाल कर इसमें से कुछ मामलों को उठाया जाए। केंद्र में नंबर-2 माने जाने और पीएम मोदी के करीबों कहे जाने वाले व्यक्ति को इसकी कमान मिलने से चिंतित कॉंग्रेस इस बारे में अन्य पार्टियों से भी चर्चा करेगी। अमित शाह का किसी मामले में घुसना ही उसे महत्वपूर्ण बना देता है। सहकारी संस्थाओं में सालों से जमे राजनीतिक आकाओं को पैठ अब खत्म होने की संभावना है, इसलिए उन्हें ये डर है। कॉंग्रेस के अलावा वामपंथी भी तिलमिलाए हुए हैं। CPI(M) के नेता और दो बार केरल के वित्त मंत्री रहे थॉमस इसाक भी चिंतित हैं। चार बार के विधायक ने कहा कि इसका कुछ गलत उद्देश्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने गुजरात के सहकारी बैंकों पर 'कब्जा' किया और 'श्वेत क्रांति' के अग्रदूत जॉर्ज कुरियन को 'गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ' से बाहर कर दिया। उन्होंने वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करने का भी विरोध किया।

सहकारिता राज्यों का विषय, केंद्र कब्जा करना चाहता है

दरअसल, इस रिपोर्ट के लागू होने से सहकारी रजिस्ट्रार से शहरी बैंकों की बागडोर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपने के बाद प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। उनका कहना है कि इससे सहकारी बैंक अपंग हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ जन-आंदोलन की जरूरत है क्योंकि इससे ये ढाँचे पर प्रहार होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता राज्यों का विषय है और केंद्र इस पर कब्जा करना चाहता है। अब हम आपको इन दलों की चिंता का कारण बताते हैं। असल में जिन दो राज्यों में सहकारिता पर सबसे अधिक ज्यादा राजनीतिक कब्जा है, वो हैं महाराष्ट्र और केरल। जहां एक जगह शरद पवार की 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी' ने चीनी मिलों से लेकर कई सहकारी संस्थाओं में पैठ बनाई हुई है, केरल में यही काम CPI(M) ने किया है। हजारों करोड़ रुपयों के इस क्षेत्र में सरकार का घुसना इन नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। केरल में सहकारी का घुसना इन नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। केरल में सहकारी आंदोलन, खासकर इसका बैंकिंग क्षेत्र वहां की सत्ताधारी वामपंथी दलों के नियंत्रण में ही है। केरल और महाराष्ट्र में ये सहकारी संस्थाएं वित्तीय रूप से काफी मजबूत हैं और इनका एक बड़ा नेटवर्क है।